held by the Law Ministry, and secondly the authority to revise is also considered in the context of *bona fides* and *mala fides* and it has been stated that the Iron and Steel Controller had satisfied himself as to the *bona fides* of the case, and the revenue authority should treat the CCP so amended as valid *ab initio*.

Shri S. K. Sambandhan: Generally, the goods are confiscated if they are not found in the licence.

श्री द्वा० नाथ तिवारी : हमारे माननीय इस्पात मन्त्री जी का व्यवहार भी इस्पात के समान है । अमीं चन्द प्यारेलाल का प्रश्न बार बार हाउस के सामने आ चुका है , मन्त्री जी मेम्बरों के साथ इस्पात जैसा व्यवहार न करके, अमींचन्द प्यारेलाल के साथ इस्पात जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं तथा ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं लेते हैं जिससे कि हाउस भी सटिस्फाइड हो और वे भी कोई गड़बड़ी न कर सकें ?

डा० चन्ना रेड्डी : जैसा मैंने पहले कहा है कि इस मामले को सरकार एन्क्वायरी कमेटी के सुपुर्द किया गया है, एन्क्वायरी हो रही है । इसके अलावा और कोई स्टेप लेने की या तो आवश्यकता नहीं है या मुश्किल भी है । एन्क्वायरी कमेटी के सामने जो काम है, उसको जल्द पूरा कराने के लिये पूरे स्टेप लिये जा रहे हैं ।

श्री कामेश्वर सिंह : जो जरूरी कागजात सरकार कमेटी को नहीं मिल पाये थे, व उनको अभी तक मिले हैं या नहीं, अगर फाइलों में कोई गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुई है ?

डा० चन्ना रेड्डी : जिन फाइलों की सरकार एन्क्वायरी कमेटी को जरूरत है, वह उनको पहुंचाई जा रही है, इसमें कागजात के मिस होने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री कामेश्वर सिंह : कुछ जरूरी फाइलें-जिन से लोगों को बहुत घाटा होगा, उनको हटा दिया गया है और सरकार कमेटी को वे फाइलें नहीं दी गई हैं ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस किस्म की कोई बात मिनिस्ट्री के सामने नहीं आई है । यदि आपके पास ऐसी कोई बात हो तो मुझे भेज दें, मैं विचार करूंगा ।

Shri Hem Barua: In view of the fact that there are serious allegations of involvement in shady deals against this firm called Aminchand Pyarelals and there have been persistent demands on the floor of this House to blacklist this firm, may I know the basic reasons why Government considered it proper to liberalize their attitude towards this firm as evidenced in this particular deal?

An hon. Member: Donations.

Dr. Chenna Reddy: The attitude towards this firm is not liberalised, but as far as the question of putting it in the black list and stopping business with it is concerned, they have approached the Calcutta High Court, and the Calcutta High Court has issued a stay order.

Shortage of Cycle Tyres and Tubes

*845. **Shri R. S. Vidyarthi:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that there is a great scarcity of popular brands of cycle tyres and tubes in the market while large stocks are available in the black-market in Delhi; **and**

(b) if so, the reasons therefor, and the steps taken to prevent such anti-social activities in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Bhanu Pra-

kash Singh): (a) Yes, Sir. Government's attention was drawn to the shortage of popular brands of cycle tyres and tubes.

(b) The main reason for such shortage is consumers' preference for certain brands of cycle tyres and tubes like Goodyear, India Super and Dunlop manufactured by M/s. Dunlop India Ltd. A number of steps have been taken by Government to ensure that popular brands of cycle tyres and tubes are available to genuine consumers from the authorised dealers and Consumer Cooperative Stores at Companies' retail prices. A statement showing the steps taken in this regard is laid on the Table of the House [*Placed in Library See No.* LT-855/67].

श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि दिल्ली में टायर तथा ट्यूब्स के एसेन्शल कमाडिटीज एक्ट के परव्यू में कब से लिया है तथा आज तक इस में कितने केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं, उन में से कितनों को सजा हुई है तथा कितनों को छोड़ दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : इस के बारे में अगर आप अलग से सवाल पूछेंगे तब जवाब दे सकूंगा। फिर भी 1966 में जब हमारे पास सब से पहले कम्पलेंट आई तो हमने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से इस के बारे में पूछा और उस के बाद हम ने जो स्टेप्स लिये तब से कोई कम्पलेंट नहीं आई।

जैसा कि सवाल के जवाब में बताया गया है कि एब्रेज तौर पर टायर-ट्यूब्स की शार्टेज नहीं है लेकिन सब लोग डनलप के बने हुए टायर-ट्यूब्स चाहते हैं। आनरेबिल मेम्बर्स जानते हैं कि डनलप 50 परसेन्ट से थोड़ा ऊपर टायर बनाते हैं 40 परसेन्ट से ऊपर ट्यूब्स बनाते हैं—यह सब को देने के लिये काफी नहीं है, सब इसे ही मांगते हैं इस वजह से इस में जरूर कमी होगी। गवर्नमेन्ट ने यह फैसला किया है कि उन के 10 परसेन्ट प्रोडक्शन को कोआपरेटिव सोसायटीज को दिया जायेगा, जिनके जरिये कनज्यूमर्स को मिल सकेगा। इस के अलावा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का लाइसेन्स के बेसिज पर थानों में साइकल के लाइसेन्स और रिक्शा के लाइसेन्स के बेसिज पर भी टायर-ट्यूब देने का इरादा है और उसी के मुताबिक उन को दिया भी जा रहा है। रिक्शावालों को साल भर में 12 टायर और ट्यूब मिलती हैं।

श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में टायर-ट्यूब्स की जितनी जरूरियात है, चाहे वह निर्धारित मूल्य पर मिले अथवा काले-बाजार से मिले लोगों को अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है तथा जो सप्लाई मैन्यूफेक्चरर्स से कोआपरेटिव सोसायटीज को या होल सेल डीलर्ज को आती है, वह सब की सब मध्य प्रदेश या यू० पी० को चली जाती है? मैं जानना चाहता हूं कि इस को रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई प्रयास किया है? सरकार एसेन्शल कमाडिटीज एक्ट के तहत अभी तक एक भी केस रजिस्टर नहीं कर सकी है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह ख्याल गलत है कि जितने टायर ट्यूब आते हैं, वे मध्य प्रदेश चले जाते है। जैसा मैंने कहा कि 1966 में जब हमारे पास कम्पलेंट आई, हमने ने साइकल डीलर्स और साइकल एसोशियेशन वालों की एक मीटिंग बुलाई थी, उन से बातचीत कर के ऐसा इन्तजाम किया गया कि जितनी भी चीजें मैन्यूफेक्चरर्स से आती है वे यहां के लोगों को मिल सकें।

Shri Manubhai Patel: I am the latest victim of this so-called or artificial shortage of motor cycle tyres and tubes. For the last two days I have been trying my best to secure a tube to replace my punctured tube. I wander from shop to shop, but nobody is willing to give me a motor

cycle tube, and looking at my clothes they do not sell it at the blackmarket rate also. Since I cannot use my motor cycle, I have to depend on bus for transport. Under the circumstances, will the Minister arrange to issue motor cycle tubes to card-holders and till this is done, will he please arrange to get me a tube from somewhere?

Shri F. A. Ahmed: The question relates to scarcity of cycle tyres and tubes and not motor cycle tubes.

Shri Manubhai Patel: They are the same, not much difference.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि टायर-ट्यूब्स की कमी नहीं है जिस बाड के टायर ट्यूब की आप बात करते हैं वह भी जितना मंत्री महोदय चाहें, मिल सकता है लेकिन ब्लैक मार्केट में मिलता है और ब्लैक मार्केट की कीमत तीन गुना ज्यादा है। 1966 में आपने जो मीटिंग बुलाई उस के बाद तो टायर-ट्यूब्स की हालत और ज्यादा खराब हो गई। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जिन कोआपरेटिव सोसाय-टीज या डीलर को आप इस का परमिट देते हैं तथा जो डायरेक्टली कन्ज़्यूमर्स को देते हैं, अध्यक्ष महोदय वह उन के पास नहीं पहुंच पाता है, होता क्या है—4 टायर कन्ज़्यूमर को दिये फिर 15 टायर बोगस नाम लिख कर रसीद काट देते हैं। क्या आप इस की एनक्वायरी करायेंगे तथा इस के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिये कोई और कदम उठायेंगे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक एनक्वायरी का ताल्लुक है अगर इस को इन्फर्मेशन दी जायगी, तो जरूरी करायेंगे। लेकिन मैं आनरेबिल मेम्बर से कहना चाहता हूं कि इस का ताल्लुक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से है, चन्द दिन हुए मैंने उनको बुलाया था और इस की बाबत बात की थी। उन्होंने मुझ को साफ तौर पर बताया कि 1966 के बाद से कोई कम्पलेंट नहीं आई है कि ब्लैक मार्केट में टायर-ट्यूब्स बिक रही हैं। जब से उन्होंने ऐसा इन्तजाम किया है कि लाइसेन्स के ऊपर एन्डोर्स करना पड़ेगा कि उन को टायर-ट्यूब मिला है, तब से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। फिर भी कोई स्पे-सिफिक केस हो तो मुझे बताइये, मैं जरूर एन्क्वायरी कराऊंगा।

Shri Chintamani Panigrahi: Because co-operatives are not there, may I know how the tyres and tubes allotted to different States are sold? Do Government get reports from different States on this and also whether Government is aware that they are being sold at higher or blackmarket prices in those States?

Shri F. A. Ahmed: I have not got the figures indicating the quantity of tyres and tubes allotted to every State. They are allotted on the basis of their requirement, subject to the availability of these tyres and tubes

Shri Krishna Kumar Chatterji: Our difficulty is this. The answers supplied by our Ministers are compiled by officers and they have no bearing on the realities. That is the state of affairs in our State also. The difficulty is that in blackmarket, you can get any quantity of tyres and tubes quite often Will the Minister consider appointing a high-power committee to go into all these things? That is what is needed?

Shri F. A. Ahmed: The hon Member must realise that this is an essential commodity and declared as such under the Essential Commodities Act. Complete power and authority in respect of distribution had been delegated to the State Government; this power is not exercised by the Central Government but by the State Government. Here the question was with regard to the Delhi Administration. If information with regard to other States is asked for, I shall send for that information and place it before the House.

श्री राम चरण : उत्तरप्रदेश के अन्दर रिक्शा चलाने वाले बहुत लोग हैं लेकिन वहां पर साइकिल रिक्शा के एक टायर व ट्यूब उन बेचारों को ब्लैक में 30 रुपये का मिलता है तो क्या मंत्री जी इस स्थिति में सुधार करेंगे ताकि वहां के रिक्शा चलाने वालों को कंट्रोल्ड रेट पर टायर व ट्यूब मिल सकें जिससे कि वह इस कठिनाई से बच सकें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : रिक्शा का जहां तक ताल्लुक है जैसा मैंने पहले कहा दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा आर्डर पास किया है कि हम एक साइकिल रिक्शा पुलर को पर क्वार्टर दो टायर और दो ट्यूब मिलेंगे और जो उन को साइलेंस मिलता है उस के ऊपर वह इंडोर्स भी करा लेंगे । अगर ऐसा नहीं हुआ है और कोई केस मेरे नोटिस में लाया जायेगा कि इस हुक्म के मुताबिक टायर व ट्यूब रिक्शा पुलर्स को नहीं मिल रहे हैं तो मैं उस की अवश्य इनक्वायरी कराऊंगा । बाकी माननीय सदस्य ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल किया है तो उस के बारे में मेरे पास अभी इनफारमेशन नहीं है बहरहाल मैं उस के बारे में इनफारमेशन मंगाऊंगा और उसे देखूंगा ।

श्री अ० लि० सहगल : यह बात सच है कि साइकिल के टायरों और ट्यूबों का उतना उत्पादन नहीं हो रहा है जितनी कि उनकी डिमांड है लेकिन उस के अलावा जो अभी मैनुफैक्चरर्स के द्वारा अपने प्रोडक्शन का 10 परसेंट माल कमर्शियल सप्लाईज के लिये कोआपरेटिव स्टोर्स को देना तय पाया गया है क्या इस परसेंट को बढ़ाने के बारे में भी कोई तजवीज सरकार के सामने आई हुई है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह बात सच है कि जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है । जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया सारी दिक्कत यह है कि हर कोई चाहता है कि उसे इनलैंड के ही टायर व ट्यूब मिलें और अगर लोग और भी अनेकों कम्पनियों द्वारा तैयार किये जाने वाले टायर ट्यूबों को लेने लगें तो यहां कोई कमी नहीं है । मैं आप को बतलाऊं कि सन् 1961 में जहां साइकिल के टायर 11 मिलियन के करीब बनते थे अब वह 19 मिलियन मैनुफैक्चर होते हैं । इसी तरह जहां सन् 62-64 में 87 हजार टायर ऐक्सपोर्ट किये गये वहां सन् 65–66 में 4 लाख 46 हजार ऐक्सपोर्ट किये । इसलिये दिक्कत यही है कि एक ही ब्रांड के लोग टायर ट्यूब लेना चाहते हैं और वह उतने नहीं हैं जितने कि लोग चाहते हैं । बाकी जो यह दस परसेंट वाली बात है उस पर हम गौर करेंगे ।

Idle Capacity in Industry

*848. **Shri S. S. Kothari:**
Shri P. Ramamurti:
Shri A. K. Gopalan:
Shri D. N. Patodia:
Shri C. C. Desai:
Shri R. Barua:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether a survey of the idle capacity in the industry was recently conducted by any official or semi-official body;

(b) if so, the broad findings thereof; and

(c) the action Government purpose to take to ensure the utilisation of such idle capacity?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh): (a) Yes, Sir. A survey on under-utilisation of industrial capacity in India was conducted by the National Council of Applied Economic Research in 1965. The report on the survey was published in October, 1966.

(b) The Council has come to the conclusion that there is a continuing